प्राकृतिक संसाधन लेखांकन

संदर्भ

सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (GASAB) के अध्यक्ष ने कहा है कि वह नवंबर के मध्य तक एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जो 28 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में खनिज और ऊर्जा संसाधनों के लिए संपत्ति खातों को अधिकृत करेगा।

मुख्य बिंदु

• परिसंपत्ति खातों में 34 प्रमुख खनिजों, 58 लघु खनिजों और सभी चार जीवाश्म ईंधन के विवरण शामिल होंगे।
• रिपोर्ट देश में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की एक पूरी तस्वीर देगी और नीति निर्माताओं को सूचित नीतिगत निर्णय लेने और उचित हस्तक्षेप करने में मदद करेगी।
• भारत चार प्रकार के संसाधनों के लिए राष्ट्रीय स्तर के परिसंपत्ति खाते तैयार कर रहा है:
खनिज और ऊर्जा संसाधन।
जल संसाधन।
भूमि संसाधन।
वानिकी और वन्यजीव संसाधन।
• संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और पर्यावरण लेखा प्रणाली (एसईईए) को अपनाया (2012) - जो एनआरए के लिए नवीनतम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ढांचा है।

एसडीजी के साथ लिंक

• भारत सितंबर 2016 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प - "विश्व को बदलना, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा" का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
• इसके लिए प्राकृतिक संसाधन खाते (एनआरए) तैयार करने की आवश्यकता है।
• 17 में से चार लक्ष्य सीधे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उनके लेखांकन से संबंधित हैं।

GASAB के बारे में

• इसका गठन 2002 में किया गया था और यह सीएजी का हिस्सा है।
• यह राज्य सरकारों को संपत्ति खाते तैयार करने में मदद कर रहा है और उन्हें एनआरए के आसपास अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप मदद कर रहा है।

पायलट ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियाँ

संदर्भ

नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी) ने "पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज" के विकास के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

• यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में बिजली क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के देश के संकल्प के अनुरूप है। कारगिल जिले के लिए हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, कारगिल में उत्पन्न हाइड्रोजन का उपयोग गतिशीलता के लिए ईंधन कोशिकाओं में किया जाएगा जो कारगिल के स्थानीय क्षेत्र में 8 घंटे तक दो बसें चलाने में सक्षम होगी।
• एनएचपीसी विभिन्न क्षेत्रों जैसे गतिशीलता, परिवहन, हीटिंग और माइक्रो-ग्रिड में लद्दाख क्षेत्र की हाइड्रोजन आवश्यकता की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाएगी और बाद में समझौता ज्ञापन पर अलग से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

महत्व

• ये दो पायलट परियोजनाएं हरित हाइड्रोजन के भविष्य के विकास और परिवहन/हीटिंग क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए एक रोडमैप तैयार करेंगी और
• यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के युवाओं के लिए विभिन्न राजस्व धाराओं और रोजगार के अवसरों का निर्माण करते हुए हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करेगा।

हरा हाइड्रोजन

• यह अक्षय ऊर्जा या कम कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन काफी कम होता है।

भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन

संदर्भ

हाल ही में स्वदेशी अंतरिक्ष स्टार्टअप, अग्निकुल कॉसमॉस ने रॉकेट इंजन बनाने के लिए समर्पित देश का पहला निजी कारखाना खोला।

मुख्य बिंदु

• नई सुविधा 3डी प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और अपने इन-हाउस रॉकेट के लिए इंजन विकसित करेगी।
• यह सुविधा वर्तमान में हर हफ्ते दो रॉकेट इंजन तक बना सकती है।
• इससे यह अपने दो चरणों वाले प्रक्षेपण वाहन, अग्निबाण के प्रक्षेपण के लिए पर्याप्त इंजन बनाने sमें सक्षम होगा, जो इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है।

अग्निबाण:

• यह एक अल्ट्रा-लाइट लॉन्च व्हीकल है, जो इसरो के आगामी छोटे, हल्के वाणिज्यिक रॉकेट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) से भी हल्का है।
• जबकि एसएसएलवी लगभग 300 किग्रा का पेलोड ले जा सकता है, अग्निबाण 100 किग्रा तक के पेलोड को पृथ्वी से 700 किमी तक की निचली पृथ्वी की कक्षाओं (एलईओ) तक ले जाने में सक्षम होगा।

महत्व:

चूंकि उपग्रहों को लॉन्च करने वाली कंपनियों और संगठनों की अब रूसी सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, और भारी रॉकेटों पर लॉन्च करना महंगा हो सकता है, छोटे कक्षीय लॉन्च वाहन भारत को निकट भविष्य में उपग्रह लॉन्च ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा हासिल में मदद कर सकते हैं।

जमानत कानून सुधार

संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, केंद्र से यू.के. के जमानत अधिनियम का हवाला देते हुए, जमानत की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया कानून लाने का आग्रह किया।

सुप्रीमकोर्ट की टिप्पणियां

• गिरफ्तारी का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। जमानत नियम और जेल अपवाद होनी चाहिए , जो कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
• दोषी साबित होने तक बेगुनाह होने के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
• सीआरपीसी की धारा 41 (पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार देता है) और धारा 41ए (पुलिस के सामने पेश होने की प्रक्रिया से संबंधित है) के उल्लंघन में अनुचित गिरफ्तारियां की जाती हैं।
• गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया और जमानत याचिकाओं के निपटारे की समय सीमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
• जमानत याचिकाओं का निपटारा दो सप्ताह के भीतर करना होगा, जब तक कि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य न हों।
• अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका पर छह सप्ताह के भीतर फैसला किया जाना है।
• आरोपी को कुछ स्थितियों में अदालत के अपने विवेक पर जमानत दी जा सकती है।

वर्तमान प्रावधान

• जमानत सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।
• अपराधों को जमानती और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• धारा 436 के तहत जमानती अपराधों में जमानत एक अधिकार है और जमानत के साथ या बिना जमानत के मुचलके के बाद पुलिस या अदालत आरोपी को रिहा करने के लिए बाध्य है।
• गैर-जमानती अपराध के लिए, एक आरोपी अधिकार के रूप में जमानत का दावा नहीं कर सकता है। विवेकाधिकार न्यायालयों के पास है।
• धारा 437 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें अदालतें गैर-जमानती अपराधों के लिए जमानत दे सकती हैं। प्रावधान अदालत को 16 साल से कम उम्र के आरोपी, जो बीमार है, या एक महिला है, को जमानत देने पर विचार करने का आदेश देता है।

• धारा 41 एक संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी से संबंधित है जहां सजा एक अवधि के लिए कारावास है जो सात साल से कम हो सकती है।
• धारा 41ए उन मामलों में एक पुलिसकर्मी के समक्ष पेश होने की सूचना से संबंधित है जहां गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।
• एक पुलिस अधिकारी को व्यक्ति को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार न करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

नामसाई घोषणा

संदर्भ

असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 123 गांवों से जुड़े अंतर-राज्य सीमा विवाद को कम करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

• असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किमी की अंतर-राज्यीय सीमा साझा करता है।
• 1960 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा 29 टोपो-शीट्स पर दिखाई गई सीमा रेखा को अरुणाचल प्रदेश-असम सीमा के पुनर्सीमांकन के आधार के रूप में लिया जाएगा।
• असम-मेघालय सीमा विवाद के समाधान के लिए मॉडल का अनुसरण किया जाना है।
• राज्यों ने 123 गांवों के संयुक्त सत्यापन के लिए सीमा के दोनों ओर के जिलों को कवर करते हुए 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया।
• ये समितियां ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रशासनिक सुविधा, निकटता और लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अंतर-राज्यीय सीमा को चित्रित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को सिफारिशें करेंगी।
• नामसाई दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है।

अरुणाचल प्रदेश का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास

• 1912-1913 में, ब्रिटिश सरकार उत्तर-पूर्व फ्रंटियर ट्रैक्ट्स (एनईएफटी) को तराशने के लिए स्वदेशी लोगों के साथ काम करने में सक्षम थी।
• जब भारत स्वतंत्र हुआ, एनईएफटी 26 जनवरी, 1950 तक असम सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया।
• तब भारत सरकार ने इसे "बहिष्कृत क्षेत्र" के रूप में शासित करने का निर्णय लिया, जिसमें असम के राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे।
• 1954 में, इस क्षेत्र को नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एनईएफए) के रूप में नामित किया गया था। पहले इसे विदेश मंत्रालय के अधीन लाया गया और अगस्त 1965 में प्रशासन को गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
• इसने 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया और 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

अन्य महत्वपूर्ण खबरें

सघन मिशन इन्द्रधनुष

सन्दर्भ

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अनुमानित 30 लाख बच्चों को COVID-19 महामारी के कारण 2020 में DTP वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिल सकी।

प्रमुख बिंदु

• फरवरी-21 में शुरू किए गए गहन मिशन इंद्रधनुष - 3.0 ने न केवल वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया बल्कि 2021 में ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हे DTP वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिल सकी को घटाकर 27 लाख कर दिया।
• सरकार ने फरवरी 2022 में IMI 4.0 लॉन्च किया है।
• COVID-19 महामारी के कारण उभरी हुई कमियों को दूर करने के लिए बिना टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से टीका लगाए गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने की योजना बनाई गई है।
• भारत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.7 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करता है जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है।

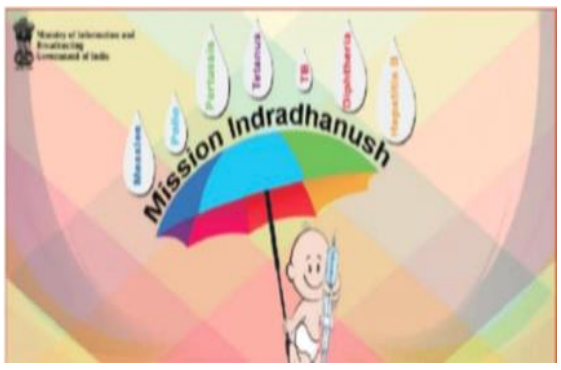

CAATSA

सन्दर्भ

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) में एक विधायी संशोधन पारित किया, जिसने दंडात्मक सीएएटीएसए प्रतिबंधों के लिए भारत-विशिष्ट छूट को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• हाउस वोट भारत के लिए एक कदम आगे है। CAATSA के तहत केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ही छूट दे सकते हैं।
• काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए) अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो 2014 में क्रीमिया के रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के जवाब में रूस से प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदते हैं।
• इसे 2017 में लाया गया था।
• रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, यह आशंका जताई गई है कि इसे खरीदने के लिए अक्टूबर-2018 में रूस के साथ 5 अरब डॉलर के सौदे पर भारत पर लगाया जा सकता है।

एसडीजी 15

सन्दर्भ

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास रिपोर्ट, 2022 के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका में कम से कम 12 देशों में SDG-15 पर समग्र प्रगति पिछड़ गई है।

मुख्य विचार

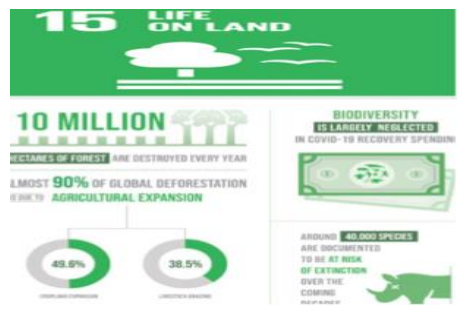

• लैटिन अमेरिका और विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में भारी नुकसान के साथ वैश्विक वनावरण वैश्विक स्तर पर सिकुड़ता जा रहा है।
• इस सिकुड़न को टिकाऊ वन प्रबंधन में रिवर्स प्रोग्रेस कहा जाता है।
• SDG-15 2030 तक भूमि पर जीवन की रक्षा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
• एसडीजी 15.2 का लक्ष्य 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए जंगलों की बहाली और वैश्विक स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना है।
• एसडीजी लक्ष्य 15.5 के तहत, दुनिया को 2020 तक संकटग्रस्त प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना, संरक्षित करना और रोकना था।

केंद्र कानूनी मेट्रोलॉजी में संशोधन करता है

सन्दर्भ

हाल ही में केंद्र ने व्यापार करने में आसानी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 में संशोधन किया है।

मुख्य विचार

• उद्योग को क्यूआर कोड के माध्यम से सूचना को डिजिटल रूप में घोषित करने की अनुमति देने के लिए संशोधन।
• उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) (दूसरा संशोधन) नियम 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एक वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य घोषणाओं को घोषित करने की अनुमति दी है, यदि पैकेज में ही घोषित नहीं किया गया है।
• यह पैकेज में लेबल पर महत्वपूर्ण घोषणाओं को प्रभावी ढंग से घोषित करने की अनुमति देगा जबकि अन्य वर्णनात्मक जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से उपभोक्ता को दी जा सकती है।
• इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित सभी पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं को पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज), नियम 2011 के अनुसार सभी अनिवार्य घोषणाओं को घोषित करना आवश्यक था।

आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सन्दर्भ

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक इंडोनेशिया (BI) ने बाली इंडोनेशिया में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

महत्व

- इस समझौता ज्ञापन के साथ, आरबीआई और बीआई दो केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- भुगतान प्रणाली, भुगतान सेवाओं में डिजिटल नवाचार सहित केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करना।
- धन शोधन रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा (एएमएल-सीएफटी) विकसित करना।
- एमओयू को नीतिगत संवाद, तकनीकी सहयोग सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्य के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा।
- समझौता ज्ञापन कुशल भुगतान प्रणाली विकसित करने और सीमा पार भुगतान कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए बेहतर आधार प्रदान करेगा।

एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022

सन्दर्भ

हाल ही में एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

Rank	Institution	Score
1	Indian Institute of Technology-Madras	87.59
2	Indian Institute of Science, Bengaluru	83.57
3	Indian Institute of Technology-Bombay	82.35
4	Indian Institute of Technology-Delhi	82.22
5	Indian Institute of Technology-Kanpur	77.83
6	Indian Institute of Technology-Kharagpur	75.94
7	Indian Institute of Technology-Roorkee	71.48
8	Indian Institute of Technology-Guwahati	69.75
9	All India Institute of Medical Sciences, Delhi	69.57
10	Jawaharlal Nehru University, Delhi	67.25

- एनआईआरएफ ढांचा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के रैंक के द्वारा तैयार किया गया था।
- पुराने रिकॉर्ड को जारी रखते हुए आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
- एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 के लिए 5 प्रमुख पैरामीटर - टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन परिणाम, आउटरीच और इंक्लूसिविटी और पीयर परसेप्शन पर विचार किया जाता है।

नए एनएसई प्रमुख

सन्दर्भ

बाजार नियामक सेबी ने आखिरकार नए एनएसई प्रमुख के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के नए एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभालने का रास्ता साफ कर दिया है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में:

- यह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है।
- वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (डब्ल्यूएफई) द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए बनाए गए आंकड़ों के अनुसार, एनएसई नकद इक्विटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है।
- एनएसई का प्रमुख सूचकांक, निफ्टी 50, एक 50 स्टॉक इंडेक्स भारत और दुनिया भर के निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार के बैरोमीटर के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
- NSE द्वारा NIFTY 50 इंडेक्स को 1996 में लॉन्च किया गया था।

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड.

सन्दर्भ

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स (ZCZP) को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है।

मुख्य बिंदु

- ज़ीरो कूपन-ज़ीरो प्रिंसिपल: यह एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा जारी किया गया एक उपकरण है जो कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत (सेबी) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) सेगमेंट के साथ पंजीकृत होगा।
- यह प्रस्तावित किया गया है कि ZCZP का न्यूनतम निर्गम आकार ₹1 करोड़ होगा जबकि न्यूनतम आवेदन आकार ₹2 लाख होगा।
- महत्व: यह कॉरपोरेट सहित कई संगठनों को सामाजिक जिम्मेदारी के लिए चिह्नित अपने फंड का उपयोग करने में मदद करेगा और गैर-लाभकारी संगठनों को अधिक पारदर्शी तरीके से धन प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
- सरल शब्दों में, ZCZP के तहत न तो किसी ब्याज का भुगतान किया जाता है और न ही मूलधन का भुगतान किया जाता है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare